दैनिक भारत कि
तामीर
संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

बीड (महाराष्ट्र) वर्ष-१ ला अंक-२११ वा मंगळवार ४ मार्च २०२५ RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 किमत : २ रूपये पन्ने - ४

जो चुप रहेगी ज़ुबान-ए-खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का!

मुंडे इसतेफा दो, मुख्यमंत्री का आदेश

मुंबई:(संवाददाता)सरपंच संतोष देशमुख की नृशंस हत्या के चौंकाने वाले फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राज्य में फिर से आक्रोश की लहर दौड़ गई है। इस घटना के मद्देनजर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अन्न व नागरी आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे को इस्तीफा देने का आदेश दिया है।

सोमवार देर रात इस मामले से जुड़े फोटो सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। देवगिरी बंगले पर देर रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे और मंत्री धनंजय मुंडे के बीच अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस ने धनंजय मुंडे से इस्तीफा देने को कहा। सूत्रों के अनुसार, आज धनंजय मुंडे अपने मंत्री पद से इस्तीफा सौंप सकते हैं।

धनंजय मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड मुख्य आरोपी

सरपंच संतोष देशमुख हत्या मामले का मुख्य सूत्रधार वाल्मीकि कराड धनंजय मुंडे का करीबी सहयोगी बताया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से वह धनंजय मुंडे के चुनावी प्रचार और जिले में उनके राजनीतिक कार्यों को संभालने का काम करता था। संतोष देशमुख की हत्या के मामले में वाल्मीकि कराड का नाम सामने आने के बाद से ही धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग उठ रही थी। हालांकि, उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने उनका बचाव करते हुए कहा था कि धनंजय मुंडे का इस हत्या मामले से कोई सीधा संबंध नहीं है।

फडणवीस ने बदली रणनीति, इस्तीफे के लिए मजबूर हुए मुंडे

इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर कहा था कि यह उनकी पार्टी का फैसला होगा। लेकिन, जब सोमवार को संतोष देशमुख की हत्या के भयावह फोटो सामने आए, तो राज्यभर में रोष और विरोध बढ़ गया। इस बढ़ते जन आक्रोश के चलते अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को धनंजय मुंडे का इस्तीफा लेना पड़ा।

अब देखना यह होगा कि धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद इस मामले में आगे क्या राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं।

महाराष्ट्र में बुनियादी सुविधाओं के लिए ६,४८६ करोड़ का प्रावधान-अजित पवार

मुंबई, ३ मार्च (प्रतिनिधि) - महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र २०२५ आज से शुरू हो गया। पहले दिन विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसके बाद विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बजट सत्र के पहले ही दिन राज्य के ग्रामीण इलाकों में घर, कृषि पंपों के लिए बिजली दरों में छूट और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास से संबंधित अतिरिक्त मांगें विधानसभा में पेश की गईं।

६,४८६ करोड़ का बजट प्रावधान

इस दौरान राज्य के वित्त मंत्री अजित पवार ने ऐलान किया कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ६,४८६.२० करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें से राज्य सरकार पर वास्तविक वित्तीय भार ४,२४५.९४ करोड़ होगा।

किन योजनाओं को मिलेगा फायदा?

अजित पवार ने द (माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म) पर भी इस घोषणा को साझा किया। उन्होंने बताया कि बजट में ग्रामीण विकास और लोकहित की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसमें शामिल हैं:

१. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में घरों का निर्माण। २. मुख्यमंत्री बळीराजा बिजली दर छूट योजना, जिससे कृषि पंप ग्राहकों को बिजली बिल में राहत मिलेगी। ३. केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत सड़क और पुल निर्माण के लिए ब्याज-मुक्त कर्ज की व्यवस्था। ४. राजर्षी छत्रपति शाहू महाराज शिक्षा शुल्क छात्रवृत्ति योजना का विस्तार। ५. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के तहत हेल्थकेयर सुविधाओं में सुधार। ६. पुणे रिंग रोड और जालना-नांदेड़ एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को गति देने के लिए फंड आवंटन। ७. गोदावरी मराठवाड़ा सिंचाई विकास निगम के लिए बळीराजा जलसंजीवनी योजना के तहत जल प्रबंधन परियोजनाएं। ८. सरकारी अनुदान योजनाओं के तहत विभिन्न विकास परियोजनाओं को निधि उपलब्ध कराना।

ग्रामीण विकास को मिलेगी मजबूती

अजित पवार ने कहा कि इस बजट से राज्य के कोने-कोने में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि इन परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा ताकि लोग जल्द से जल्द इसका लाभ उठा सकें।

शेतकऱ्यांची शिकायतों का जल्द निपटारा करें-सांसद बजरंग सोनवणे

केज में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

केज, ३ मार्च (प्रतिनिधि) - महावितरण विभाग सीधे किसानों से जुड़ा है, और यहां किसानों की कई शिकायतें आती हैं। इन सभी शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए। किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, यह सख्त निर्देश सांसद बजरंग सोनवणे ने केज में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए।

सांसद बजरंग सोनवणे ने ३ मार्च को केज तालुका के विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक पंचायत समिति कार्यालय में सुबह १०:३० बजे ली। यह बैठक लगातार चार घंटे तक चली। बैठक में उपविभागीय अधिकारी वजाळे, तहसीलदार गिडा, कार्यकारी अभियंता आंधळे, मोराळे, गटविकास अधिकारी सहित सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

कृषि और बिजली विभाग पर निर्देश

सांसद सोनवणे ने कहा कि 'मागेल त्याला सौर योजना' की अवधि छह महीने से घटाकर तीन महीने की जानी चाहिए और इसके लिए वरिष्ठ कार्यालय को पत्र भेजा जाए। कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने पीक बीमा योजना, पीएम किसान योजना की समीक्षा की और जोर देकर कहा कि किसानों को अनावश्यक परेशान न किया जाए।

उन्होंने घोषणा की कि जिले में मंडल-स्तर पर मौसम निगरानी यंत्रों को मंजूरी दिलाने के लिए पर्यावरण मंत्री से मांग की जाएगी।

पानी और सड़क व्यवस्था को लेकर नाराजगी

बैठक के दौरान केज शहर में पिछले एक महीने से जल आपूर्ति बाधित होने की समस्या पर भी चर्चा हुई। सांसद ने इसे गलत बताते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई और जल आपूर्ति योजना की तत्काल मरम्मत कर पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने अहमदपुर से चुंबळी फाटा के बीच सड़क की खराब स्थिति पर भी नाराजगी जताई। सांसद ने कहा, इस खराब सड़क के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है। इसकी पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों की है। उन्होंने इस सड़क की तत्काल मरम्मत के आदेश दिए।

भूमि अभिलेख विभाग को दी सख्त चेतावनी

सांसद सोनवणे ने भूमि अभिलेख विभाग को निर्देश दिए कि किसानों द्वारा दाखिल किए गए प्रस्तावों का तुरंत निपटारा किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों की फाइलों को अनावश्यक रूप से अटकाया गया तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, श्रावणबाळ योजना और संजय गांधी योजना को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई और अधिकारियों को त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए गए।

सांसद बजरंग सोनवणे ने अंत में अधिकारियों से कहा कि काम की गुणवत्ता से समझौता न करें और बोगस कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

महाराष्ट्र विधान परिषद की ५ सीटों के लिए २७ मार्च को द्विवार्षिक चुनाव

मुंबई, ३ मार्च (विशेष प्रतिनिधि) - केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद की ५ सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा की है। ये सीटें विधानसभा सदस्यों द्वारा मनोनीत किए जाने वाले विधान परिषद के ५ सदस्यों के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई हैं। इन सीटों के लिए २७ मार्च को मतदान होगा।

किसके स्थान पर हो रहे हैं चुनाव?

विधान परिषद के जिन ५ सदस्यों के इस्तीफे के कारण यह चुनाव हो रहा है, उनके कार्यकाल इस प्रकार थे:

आमश्या पाडवी - कार्यकाल ७ जुलाई २०२८ तक प्रविण दटके - कार्यकाल १३ मई २०२६ तक राजेश वितेकर - कार्यकाल २७ जुलाई २०३० तक रमेश कराड - कार्यकाल १३ मई २०२६ तक गोपीचंद पडळकर - कार्यकाल १३ मई २०२६ तक हालांकि, इन सभी सदस्यों का विधानसभा के लिए चयन हो गया है, जिसके कारण इन सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव आयोजित किया जा रहा है। चुनाव कार्यक्रम

चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार: १० मार्च २०२५ - अधिसूचना जारी होगी १७ मार्च २०२५ - नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि १८ मार्च २०२५ - नामांकन पत्रों की जांच २० मार्च २०२५ - नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि २७ मार्च २०२५ - सुबह ९:०० बजे से दोपहर ४:०० बजे तक मतदान २७ मार्च २०२५ (शाम ५:०० बजे के बाद) - मतगणना शुरू होगी २९ मार्च २०२५ - पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी मतदान और मतगणना प्रक्रिया इस चुनाव के तहत विधानसभा सदस्य मतदान करेंगे और उसी दिन शाम ५ बजे के बाद मतगणना होगी। २९ मार्च तक पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, ऐसा चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है।

शहर में चोरों का आतंक, बंद घर का ताला तोड़कर ढाई लाख की चोरी

बीड, ३ मार्च (प्रतिनिधि) - शहर के नेहरू नगर इलाके में एक परिवार के देवदर्शन के लिए बाहर जाने का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर २,५७,५०० कीमती माल चुरा लिया। यह घटना १८ फरवरी से १ मार्च के बीच घटी, जिसके बाद बीड शहर पुलिस थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

क्या चोरी हुआ?

पुलिस के अनुसार, रमेश नरसिंगराव त्रीमुखे अपने परिवार के साथ देवदर्शन के लिए गए थे। इसी दौरान चोरों ने उनके घर का दरवाजा तोड़कर अलमारी में रखे कीमती सामान पर हाथ साफ किया। चोरी गए सामान की सूची इस प्रकार है:

२ तोले का लॉकेट - ८०,०००

पर्स में रखे ३५,००० नकद

३ तोले की सोने की चेन - १,२०,०००

चांदी की फ्रेम - २,५००

कान के झुमके (५ ग्राम) - २०,०००

चोरी की कुल कीमत २,५७,५०० आंकी गई है।

शहर में बढ़ते अपराधों से दहशत

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से बीड शहर में अपराधों की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे स्थानीय लोग चिंतित हैं। पुलिस पर अपराध रोकने के लिए दबाव बढ़ रहा है।

पुलिस जांच जारी

घटना के बाद बीड शहर पुलिस थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है और इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि अपराधियों का पता लगाया जा सके।

महादेव मुंडे परिवारने आमरण अनशन स्थगित किया

आरोपियों की गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद लिया फैसला

बीड, ३ मार्च (प्रतिनिधि) - परळी में महादेव मुंडे हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उनकी पत्नी ज्ञानेश्वरी मुंडे ने आज से आमरण अनशन शुरू किया था। उन्होंने बीड जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया था। हालांकि, अप्पर पुलिस अधीक्षक चेतना तिडके ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अनशन फिलहाल स्थगित कर दिया।

१६ महीने बाद भी आरोपी फरार

गौरतलब है कि परळी के व्यापारी महादेव मुंडे की हत्या अक्टूबर २०२३ में कर दी गई थी। इस हत्याकांड को १६ महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। मुंडे परिवार ने पुलिस से मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

आमरण अनशन का पहला दिन

महादेव मुंडे की पत्नी ज्ञानेश्वरी मुंडे ने आज से बीड जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू किया था। लेकिन पहले ही दिन अप्पर पुलिस अधीक्षक चेतना तिडके ने मौके पर पहुंचकर परिवार को समझाने का प्रयास किया। पुलिस का आश्वासन और अनशन समाप्त

अप्पर पुलिस अधीक्षक चेतना तिडके ने आश्वासन दिया कि महादेव मुंडे हत्याकांड के आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा और परिवार को न्याय मिलेगा।

इसके बाद ज्ञानेश्वरी मुंडे ने फिलहाल अनशन स्थगित करने का फैसला किया। चेतना तिडके ने उन्हें पानी पिलाकर अनशन समाप्त कराया। पुलिस प्रशासन अब इस मामले में जल्द कार्रवाई करने का भरोसा दिला रहा है।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

धनंजय मुंडे, कोकाटे के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष का हंगामा

विधान भवन की सीढ़ियों पर आंदोलन

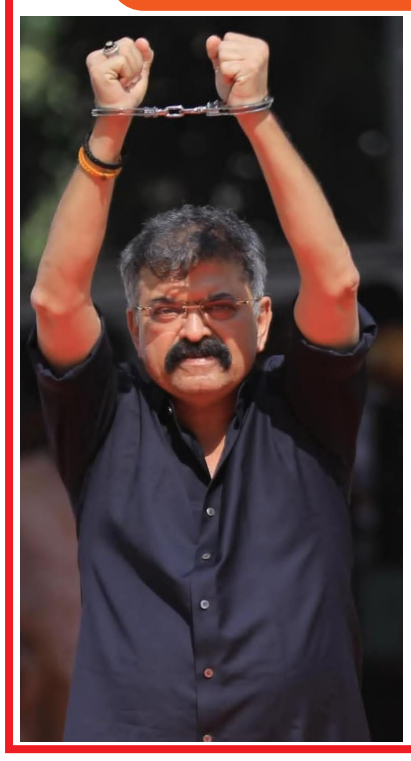

जमीर काज़ी

मुंबई, ३ मार्च:

राज्य के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई है, लेकिन पहले ही दिन विपक्ष ने विवादित मंत्रियों धनंजय मुंडे और कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे के इस्तीफे की मांग को लेकर आक्रामक रुख अपनाया। विपक्षी नेताओं ने विधान भवन की सीढ़ियों पर प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की- महाराष्ट्र में दो गुंडे, मुंडे और कोकाटे। साथ ही, विधान परिषद में भी इन दोनों मंत्रियों के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा किया गया।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा कि कोकाटे के खिलाफ मामला अभी अदालत में विचाराधीन है और अदालत के फैसले के बाद राज्यपाल और विधानसभा इस पर निर्णय लेंगे। हालांकि, विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ।

बजट सत्र के पहले दिन महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को श्रद्धांजलि देने के बाद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी नेताओं ने विधान भवन की सीढ़ियों पर बैठकर नारेबाजी की। इस दौरान विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि किसी मंत्री को दोषी ठहराए जाने के बावजूद उसे बचाया जा रहा है, जो निंदनीय है। उन्होंने सभापति से इस पर तुरंत निर्णय लेने की मांग की।

शोक प्रस्ताव के दौरान इस मुद्दे को उठाने पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई और सभापति रामराजे शिंदे ने विपक्षी नेताओं को शांत रहने की हिदायत दी। बावजूद इसके, सदन में कुछ समय तक हंगामे की स्थिति बनी रही। मुख्यमंत्री फडणवीस ने आश्वासन दिया कि कोकाटे द्वारा दायर याचिका पर कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार उचित कदम उठाएगी। इसके बावजूद, विपक्ष की नाराजगी बनी रही, और अंततः शोक प्रस्ताव पारित कर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

हाथों में हथकड़ी पहनकर विधानसभा पहुंचे जितेंद्र आव्हाड!

अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला हो रहा है - आव्हाड

राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) के नेता जितेंद्र आव्हाड सोमवार को हाथों में हथकड़ी पहनकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला कर रही है।

आव्हाड ने कहा, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसके खिलाफ केस दर्ज कर उसकी आवाज दबाई जा रही है। यह गलत है। संविधान हमें बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, जिसे छीना नहीं जा सकता। इसलिए मैंने विरोध स्वरूप यह हथकड़ियां पहनी हैं।

उन्होंने अमेरिकी सरकार की नीतियों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार की वीज़ा नीति के कारण कई भारतीय परिवार तबाह हो रहे हैं। भारतीयों को अमानवीय तरीके से विमान में भरकर भारत भेजा जा रहा है, उनके हाथों में हथकड़ियां और पैरों में जंजीरें डाली जा रही हैं। इसके खिलाफ भारत सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।

सत्ताधारी दल के नेताओं ने आव्हाड के इस प्रदर्शन को 'नौटंकी' करार दिया और इसे राजनीतिक ड्रामा बताया।

मुंडे, कोकाटे की मुख्यमंत्री से गुप्त बैठक

विवादों में घिरे मंत्री धनंजय मुंडे और माणिकराव कोकाटे ने राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में इन दोनों मंत्रियों के भविष्य को लेकर चर्चा हुई। विधानसभा में ठाकरे गुट को नेता प्रतिपक्ष का पद, परिषद में कांग्रेस को मौका महाविकास आघाड़ी के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के कारण अभी तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं हो पाई थी। हालांकि, अब यह तय किया गया है कि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के पास २० विधायक होने के कारण यह पद उन्हें मिलेगा। वहीं, विधान परिषद में कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा सदस्य हैं, इसलिए वहां कांग्रेस के किसी नेता को यह पद सौंपा जाएगा।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने बताया कि विधानसभा में भास्कररराव जाधव और विधान परिषद में सतेज पाटिल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। देर रात तक इन नामों पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है और मंगलवार को ये नाम आधिकारिक रूप से विधानसभा अध्यक्ष और परिषद सभापति को सौंपे जाएंगे।

क्या मुख्यमंत्री अन्य विभागों के घोटालेबाज ठेके भी रद्द करेंगे?-नाना पटोले का सवाल

विशेष प्रतिनिधि

मुंबई, ४ मार्च:

भाजपा-शिवसेना सरकार में तीन नेता, तीन विचारधाराएं हैं, लेकिन उनकी असली लड़ाई मलाई खाने और संपर्क मंत्री पद पाने के लिए है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे सरकार के कार्यकाल में हुए स्वास्थ्य विभाग के ठेके को रद्द कर दिया, लेकिन क्या वे अन्य विभागों में हुए घोटालों पर भी ऐसा ही कदम उठाएंगे? यह सवाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने उठाया है।

पटोले ने सोमवार को विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग की तरह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जल संसाधन, निर्माण और कृषि विभाग में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। पिछले महीने ही कांग्रेस ने कृषि विभाग में हुए कुछ घोटालों का पर्दाफाश किया था। अब मुख्यमंत्री को इन सभी भ्रष्टाचार से जुड़ी फाइलों की जांच कर ठेके रद्द करने का साहस दिखाना चाहिए।

पटोले ने कहा, हम विपक्ष में रहकर सरकार से इन सभी घोटालों पर जवाब मांगेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वे आपराधिक प्रवृत्ति के मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाएंगे, लेकिन सवाल केवल धनंजय मुंडे और माणिकराव कोकाटे का नहीं है। इस मंत्रिमंडल में ६५% मंत्री आपराधिक छवि के हैं। क्या मुख्यमंत्री सभी को बर्खास्त करने की हिम्मत दिखाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो हम इसका स्वागत करेंगे।

राज्य में कानून व्यवस्था चरमराई - पटोले

पटोले ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य में बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, केंद्रीय मंत्रियों की बेटियां भी पुलिस थानों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। बीड, परभणी और स्वारगेट जैसी घटनाओं में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। ड्रग्स खुलेआम बेचे जा रहे हैं।

पटोले ने यह भी कहा कि नागपुर अधिवेशन में भी बीड और परभणी की घटनाओं को उठाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर गलत जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि परभणी मामले को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाएगा। बीड कांड के आरोपी जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। पटोले ने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण की वजह से ही अपराधी बेखौफ हैं। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में जानबूझकर असुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक पूरी तरह अक्षम साबित हुए हैं और इसी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। पटोले ने सरकार से इन सभी मामलों पर जवाब देने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।

प्रगतिशील और विकसित महाराष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ रहा राज्य-राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन

बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से

विशेष प्रतिनिधि

मुंबई, ४ मार्च:

राज्य सरकार किसानों, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के साथ-साथ स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दे रही है। राज्य सभी वर्गों को साथ लेकर एक समावेशी, प्रगतिशील और विकसित महाराष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य कर रहा है, ऐसा प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने बजट सत्र के उद्घाटन भाषण में किया।

२६ मार्च तक चलने वाले इस सत्र में १० मार्च को उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार राज्य का बजट पेश करेंगे। पहले दिन, विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राज्यपाल ने महाराष्ट्र के भविष्य की दिशा को स्पष्ट किया और सरकार की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला।

कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार

राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में नए अवसरों का विस्तार कर रही है और किसानों के हित में निर्णय ले रही है।

सौर ऊर्जा से सिंचाई सुविधा: मागेल त्याला सौर पंप योजना के तहत ३.१२ लाख सौर पंप लगाए गए हैं। अगले पांच वर्षों में १० लाख सौर पंप किसानों को दिए जाएंगे।

प्रधानमंत्री-कुसुम और मुख्यमंत्री सौर कृषि योजना: इन योजनाओं के तहत महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बनेगा, जहां सभी कृषि पंप सौर ऊर्जा से संचालित होंगे।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना: राज्य में ९५ लाख से अधिक किसानों को लाभार्थी के रूप में चुना गया और ८७ लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध कराई गई।

फसल ऋण: २०२४-२५ के लिए ७४,७८१ करोड़ रुपये की फसल ऋण राशि वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।

जल संरक्षण: गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना के तहत १२७४ जलाशयों से ४ करोड़ घनमीटर गाद निकाली गई, जिससे ३१,००० से अधिक किसानों को लाभ हुआ।

महिलाओं और समाज के अन्य वर्गों के लिए योजनाएं

लखपति दीदी योजना: अब तक १७ लाख महिलाओं की वार्षिक आय १ लाख रुपये से अधिक हो गई है। सरकार ने २०२४-२५ तक २६ लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है।

१८ महामंडलों की स्थापना: विभिन्न सामाजिक समूहों के उत्थान के लिए १८ महामंडल स्थापित किए गए हैं, जिन्हें ५०-५० करोड़ रुपये का फंड दिया गया है।

शिक्षा और डिजिटल पहल

महाराष्ट्र को छ--उ से मान्यता प्राप्त कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या में देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है।

नासिक में राम-काल-पथ परियोजना के तहत रामायण कालीन धरोहरों को संरक्षित करने की योजना बनाई गई है।

एग्रीस्टैक - कृषि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर: इससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से मिलेगा।

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत १० वर्षों से कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है।

कैंसर रोगियों के लिए पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग कोर्स शुरू किया गया।

औद्योगिक निवेश और रोजगार

राज्यपाल ने कहा कि महाराष्ट्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (ऋऋख) के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है।

२०२५ में दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में महाराष्ट्र सरकार ने ६३ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ १५.७२ लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते किए। इससे १५ लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

राज्य सरकार औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए ३५०० एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित कर रही है।

१० एकीकृत औद्योगिक केंद्र और लॉजिस्टिक केंद्र विकसित किए जाएंगे।

युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के तहत १.३२ लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। २०२४-२५ में १० लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने और इसके लिए ५५०० करोड़ रुपये आवंटित करने का लक्ष्य।

पंडित दीनदयाल रोजगार मेले के माध्यम से १९,००० से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की योजना

नागपुर-गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत ८६,३०० करोड़ रुपये होगी।

सड़क विकास: ७४८० किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

फास्टैग अनिवार्य: १ अप्रैल २०२५ से सभी टोल नाकों पर केवल फास्टैग के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेषज्ञ वकीलों की नियुक्ति की गई है।

राज्यपाल का निष्कर्ष

राज्यपाल राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के उत्थान के लिए योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र औद्योगिक, कृषि, डिजिटल और सामाजिक क्षेत्रों में तेजी से प्रगति करता रहेगा।

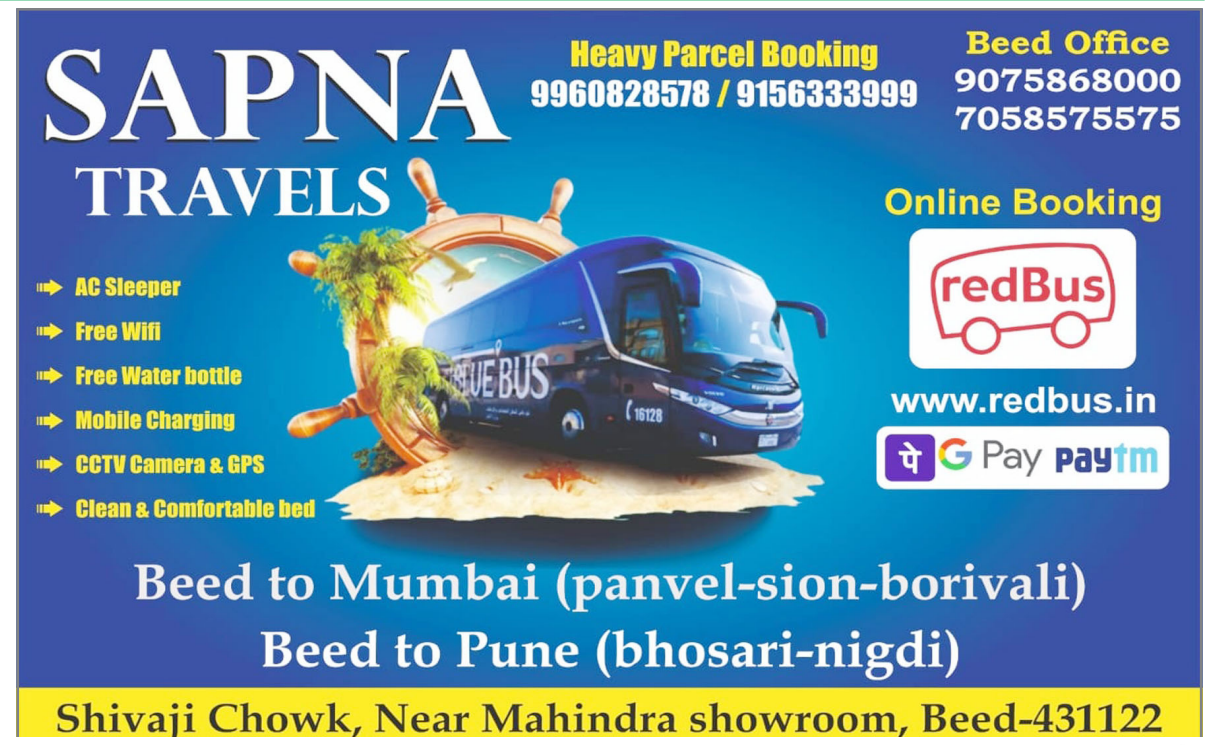

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com